

सम्पादकीय

मानसून सत्र में कृपया सार्थक चर्चा करें, हंगामा वर्तों राजनीति और नहीं लोकतंत्र के लिए शुभ

यदि संसद में सकारात्मक चर्चा नहीं होगी और कानूनों के निर्माण का मूल कार्य ढंग से नहीं बिंबा जाएगा तो पिछ कहा किया जाएगा? यह एक तथ्य है कि संसद में अब सार्थक चर्चा का अधिक देखने को मिलता है। यह न तो राजनीति के लिए शुभ है न लोकतंत्र के लिए और न ही आम जनता के लिए यह अच्छी बात है कि संसद के मानसून सत्र में सकारात्मक हमले के जवाब में पासवान के खिलाफ किए गए आरोपण सिद्धू पर चर्चा को तैयार किया गया है। इस तैयारी के अनुरूप सकारात्मक कार्य और व्यवहार होना भी चाहिए और दिखाना भी। इसी तरह विषय को भी आपरेशन सिद्धू और इससे जुड़े अन्य विषयों पर गंभीर चर्चा के लिए तत्पर दिखाना होगा। इससे संबंधित ही हुआ जा सकता कि दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सर्वदलीय बैठक में पक्ष-विषय के बीच इस विषय पर सहमति बढ़ी, क्योंकि अभी तक का अनुभव यही बताता है कि संसद सत्र के पहले आयोजित होने वाली सर्वदलीय बैठकों में कहाँ-बताया कुछ जाता है और लोकसभा एवं राज्यसभा में कुछ और देखने को मिलता है। आपत्तर पर यह कुछ और नहीं, बल्कि हल्ले एवं हंगामे के रूप में देखने को मिलता है। संसद के भीतर अथवा बाहर किसी विषय पर चर्चा में महत्वपूर्ण यह होता है कि उस पर किस इरादे से पक्ष-विषय के जेना आपनी बाबा कह रहे हैं। कई बार ये रहस्य वैसे नहीं होते, जैसे प्रचारित किए जाते हैं। कभी सत्तापक्ष विषय के विषयों को अन्वयशक समझता है और कभी विषयों के लिए विशेष अन्य जीवनीति करते दिखते हैं। अब तो ऐसा उनके उद्देश्य को पूरा करना बेहतर समझता है। इसके नवीनी में किसी भी मुद्दे पर सकारात्मक एवं सार्थक चर्चा नहीं हो पाती। स्थिति यह है कि राष्ट्रीय महत्व के कई विषयों पर भी डंग से चर्चा नहीं होती। वे या तो लंबित पड़े रहते हैं अथवा हंगामे के बीच जैसे-तैसे पास हो जाते हैं। जब ऐसा होता है तब विषय यह शोर मचाता है कि बहुमत के बल पर विषय की आवाज को दबा दिया जाया और अब तो ऐसा अक्सर सुनने को मिलता है कि देश में लोकतंत्र के नाम पर एक तरह की तानाशाही चल रही है। यह बात वह कागिस खासतौर पर कहती है, जो सचमुच तानाशाही के रखने पर चली थी। तब उसकी तानाशाही का विषयों के बाले कई दिनों के नेतृत्वों की ओर से ऐसे कई बयान दिये भी गए थे।

आज का विचार



विश्व के लिए खतरनाक होगा टैरिफ का दाव, भारत को अपनी कूटनीति पर लगाना होगा दाव

प शास्त्रीर गजनीवी की

मशहूर गजल का

मतला है—गोजरा सी

बात पर बरसों के याराने गए। पुतिन और ट्रंप के बीच हाल में कुछ ऐसा ही हुआ है। हाँ, बात के बीच हाल में कुछ ऐसा ही है।

2013 की मिस यूनिवर्स सौंदर्य प्रतिस्पर्धा को लेकर मास्को गए ट्रंप ने रूसी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रपति पुतिन की खातिर दारी से अभिभूत होकर कहा था कि वे राष्ट्रपति

ओवामा से भी अधिक प्रभावशाली हो चुके हैं। पुतिन का रंग उन पर इतना

गहरा चढ़ा कि राष्ट्रपति बनने के बाद

2018 के हेलसिंकी खिलाफ

समेतन में उन्होंने अपने खुफिया

तत्र के खिलाफ पुतिन का पक्ष लेते हुए यह मानने से इन्कार कर दिया

कि रूस ने अंतर्राष्ट्रीय और मिसाइले देना शुरू

करने का एलान किया और पुतिन

को वेतावनी देते हुए कहा कि यदि वे

50 दिनों के भीतर युद्ध विराम के लिए

राजी नहीं हुए तो रूसी माल खरीदने

वाले देशों पर 100 प्रतिशत टैरिफ

जैसे कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए

जाएं। नाटो महासंघिव मार्क रूटा ने

तो चीन, भारत और ब्राजील को सीधे

ही कह दिया कि यातो तीनों मिलकर

पुतिन को युद्ध विराम के लिए राजी

करें, अन्यथा अमेरिकी प्रतिबंधों के

लिए तैयार हो जाएं। युरोपीय संघ ने

रूस पर नए प्रतिबंध लगादिए हैं और

अमेरिकी सीनेट रूस से तेल

खरीदने वाले देशों पर 500 प्रतिशत

तक टैरिफ लगाने वाले प्रत्यावर की

तैयारी कर रही है। रूस प्रतिदिन

लगभग 70 लाख बैरल तेल का

निर्यात करता है, जिसका 47

प्रतिशत चीन खरीदता है और 38



उन्होंने कहना शुरू किया कि वे उनसे प्रतिशत भारत। रूस इस समय

दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल

उत्पादक देश है। उसके तेल की

विक्री बंद होने से दुनिया में तेल की

कीमतों में भारी बढ़ोतारी हो सकती

है, जिसका असर चीन और भारत

पर तो पड़ेगा ही, यूरोप और अमेरिका

भी उससे अचूते नहीं रह पाएंगे,

वर्षोंके तेल की कीमतों में उछल से

महंगाई बढ़ेगी और दुनिया की

अर्थव्यवस्था संकट में पड़ जाएगी।

इससे रूस का नुकसान तो तब होगा

जब चीन, भारत और ब्राजील तेल

खरीदना बंद करेंगे। हालांकि तेल

की कीमतें बदलने से रूस को फायदा

होना तुरंत शुरू हो गया है। वैसे भी

पुतिन को लगता है कि ट्रंप की धमकी

गीदंभमधकी के सिवाय कुछ नहीं है।

इसलिए पुतिन ने यूक्रेन पर 700 ड्रोन

और दर्जन भर मिसाइलों से बड़ा

हमला किया। अमेरिकी चेतावनी के

जवाब में रूसी विदेश मंत्रालय की

प्रवक्ता जखरोवा ने भी कहा कि

अल्टीमेटम, लैकमेल और

धमकियां हमें मंजूर नहीं हैं। हम

अपनी सुरक्षा और हितों की रक्षा के

लिए हर जरूरी कदम उठाएंगे।

रूसी शेरय बाजार में भी घबराहट

की जगह तेजी दिखाई दी। ट्रंप का

पुतिन से मोहर्भंग होना तो समझ में

आता है, परंतु आर्थिक प्रतिबंधों के

जिसलिए उन्होंने नाटो के जरिये

हथियार बेचने का रास्ता चुना है,

ताकि यूक्रेन अपनी रक्षा करते हुए

रूसी सेना और रक्षा तंत्र को इतनी

चोट पहुंचाता रहे कि एक दिन पुतिन

थककर बातीय तो राज्य पर लगाना हो

जाए। दूसरी ओर, पुतिन का लक्ष्य

यूक्रेन की सैनिक और खुफिया

शक्ति और रक्षा उद्योग को तोड़ा कर

उसे ऐसे नाकाम राज्य में बदल देना है

जहां रूसी हमलों के ब्याप्ति के

निये दिए गए विशेष उपकरणों की

क्षमता बढ़ी है। उन्होंने भारत के

कार्यकारी क्षमता बढ़ावा दिया है।

इसलिए उन्होंने भारत के लिए विशेष

उपकरणों की विकास तो राज्य पर

लगाना हो गया है। जब लक्ष्य

पर तो उन्होंने भारत को एक चेहरा

किया है। बता दें कि टीआरएफ पर बैन का कोई

सार्वजनिक संघर्ष हो रहा ह

